



सेंसेक्स में 207 अंकों की गिरावट

स्थानीय शेयर बाजार में मुनाफावसूली से सेंसेक्स 207 अंक की गिरावट के साथ 80,157.88 अंक पर बंद हुआ। } 14

जीएसटी घटने से छोटे व्यवसायों को होगा लाभ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खुला एवं पारदर्शी बनाएंगे। } 16

अफगानिस्तान में फिर आया भूकंप

अब तक 1400 से अधिक की मौत, 3,000 घायल, भारत ने भेजी मदद



एजेंसी नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 18 अरब डॉलर से अधिक की 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं जारी हैं और देश अब भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि 1,000 अरब डॉलर के वैश्विक चिप बाजार का दोहन करने के लिए उसको (चिप) तैयार करने से जुड़ी प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना के अगले चरण पर सरकार काम कर रही है। मोदी ने कहा वह दिन दूर नहीं जब भारत में बनो सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी भारत में तैयार, भारत में निर्मित, दुनिया के लिए विश्वव्यापी।

सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण में भारत : मोदी

एजेंसी नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 18 अरब डॉलर से अधिक की 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं जारी हैं और देश अब भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि 1,000 अरब डॉलर के वैश्विक चिप बाजार का दोहन करने के लिए उसको (चिप) तैयार करने से जुड़ी प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना के अगले चरण पर सरकार काम कर रही है। मोदी ने कहा वह दिन दूर नहीं जब भारत में बनो सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी भारत में तैयार, भारत में निर्मित, दुनिया के लिए विश्वव्यापी।



बात कही। इसमें दुनिया भर से करीब 50 देशों के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों ने शिरकत की। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की नवाचार और युवा शक्ति भी इस कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह अनूठा संयोजन एक स्पष्ट संदेश देता है, दुनिया, भारत

एजेंसी पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बिहार में कांग्रेस की हाल में संपन्न हुई वोट अधिकार यात्रा के दौरान उनकी मां को अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ है और इस घटना के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) एवं कांग्रेस को वह भले ही माफ कर दें लेकिन बिहार के लोग इन दलों को कभी माफ नहीं करेंगे। मोदी ने

पर भरोसा करती है। दुनिया, भारत में विश्वास करती है और दुनिया, भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि तेल का लोहा सोना था लेकिन चिप डिजिटल हीरा है। उन्होंने कहा कि जहां ...शेष पृष्ठ 14 पर

संक्षेप

सड़क हादसों में सात लोगों की मौत

लखनऊ। हापुड़, देवरिया, बलरामपुर और हमीरपुर जिलों में हुए सड़क हादसों में सात लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हापुड़ जिले के पिलखुवा थाना क्षेत्र में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार कार ने सोमवार देर शाम एक स्कूटी और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी सवार आरिष्म और मोटरसाइकिल सवार सचिन तथा उमेश नामक युवकों की मौत हो गई। वहीं, देवरिया जिले के सोनू घाट-महुआनी मार्ग पर मंगलवार दोपहर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिशनपुर कला गांव के निवासी निशांत शर्मा (22) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, शर्मा अपने तीन साथियों अरुण (20), मोहित यादव (14) और विपिन चौहान (22) के साथ बख्शपुर में स्थित हनुमान मंदिर गए थे, वहां से लौटते समय चारों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। घाटेला गांजी गांव के पास सड़क ...शेष पृष्ठ 14 पर

आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगा 20 हजार तक मानदेय

यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला ○ उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मिली मंजूरी

विशेष संवाददाता लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कम्पनीज एक्ट-2013 के संकशन-8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चयन तीन वर्ष के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है। इस निर्णय के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं को बेहतर अवसर देगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार और सुशासन का नया मॉडल भी स्थापित करेगा। इसके साथ ही यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 को



○ मासिक वेतन के साथ ही पीएफ और ईएसआई खातों में सीधे जायेगा पैसा ○ तीन साल तक विभाग में अपनी सेवा प्रदान कर सकेंगे कर्मचारी ○ मंत्रिमंडल ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे पर तय की स्टाम्प शुल्क की सीमा ○ लखनऊ-कानपुर मार्ग पर ई-बसों का संचालन करेंगे निजी ऑपरेटर

मंजूरी दी है। जनपद लखनऊ, कानपुर नगर तथा उसके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में ई-बसों को नेट कॉर्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर संचालित करने का निर्णय लिया है। मंत्री मंडल की बैठक में निर्वात प्रोत्साहन नीति 2025-30 व शाहजहांपुर में स्वामी शुक्रदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना समेत 15 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग इंसिस्टेंसों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि

निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे थे। लेकिन, लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थीं कि उन्हें सरकार की ओर से स्वीकृत मानदेय

जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी तय करेगा। कर्मचारियों का मानदेय 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। कर्मचारी तीन वर्षों के लिए अपनी सेवाएं दे सकेंगे। कर्मचारियों का वेतन 1 से 5 तारीख तक सीधे उनके खातों में जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान अब सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा, पहले यह राशि सर्विस प्रोवाइडर के पास चली जाती थी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी। आउटसोर्सिंग के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रावधान किया गया है। इससे बेहतर गुणवत्ता वाले और योग्य कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के तहत एएससी, एएसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को ...शेष पृष्ठ 14 पर

पहाड़ से लेकर मैदानों तक बारिश का कहर

एजेंसी नयी दिल्ली। दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, पंजाब, चंडीगढ़ हिमांचल व उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सुरक्षा कारणों से कई राज्यों में स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के झज्जर, यूपी के कई जिलों में 3 सितंबर 2025 को सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, कुछ स्थानों पर स्कूल बंद रखने का आदेश विशेष स्थानीय स्कूलों के लिए हो सकता है। इसलिए छुट्टी के संबंध में एक बार अपने विद्यालय से संपर्क जरूर करें।



राज्यीयबाद में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि 3 सितंबर को कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में यमुना के किनारे देखा गया जो खतरे का निशान पार कर गई है। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मदनपुर खादर में किसान अपनी आखिरी फसल को बचाने की कोशिश करते नजर आए, जबकि बाकी फसल नष्ट हो चुकी थी।

किसान रामशंकर ने कहा, हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है और खेत जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने रुआंसे होते हुए कहा भरे चाचा ने फसल की ...शेष पृष्ठ 14 पर

आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार

ट्रैक्टर व नाव से आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामी प्रमुख संवाददाता हरिद्वार (उत्तराखंड)। राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। हम हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से यथासंभव सहायता प्रदान की जाएगी। यह विचार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के लक्सर में आपदा प्रभावितों के स्थलीय निरीक्षण के दौरान आपदा पीड़ितों से व्यक्त किए।



राज्य में जारी भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के चलते उत्पन्न संकट की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सबसे पहले प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं। मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन अधिकारियों को तत्काल राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के ...शेष पृष्ठ 14 पर

राजस्व मामलों के निस्तारण में लखनऊ अटवल

विशेष संवाददाता लखनऊ। प्रदेश में राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनीटरिंग का असर साफ नजर आ रहा है। सीएम योगी खुद हर माह जिलेवार मामलों की समीक्षा भी करते रहते हैं। सरकार की विशेष पहल के तहत तेजी से मामलों के निपटारे की रणनीति को अपनाया गया, जिससे राजस्व विवादों के मामलों में बड़ा सुधार देखने को मिला है। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश भर में राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी देखी गयी है। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) की ओर से अगस्त माह की जारी रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में सबसे अधिक राजधानी में मामलों को निस्तारित किया गया है जबकि जनपद स्तरीय न्यायालयों में राजस्व के मामले निपटारे में एक बार फिर जौनपुर ने बाजी

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ



मारी है। बता दें कि जनपद स्तरीय न्यायालयों में राजस्व वादों के निस्तारण में पिछले दस माह से जौनपुर टॉप फाइल जिलों में बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि

राजस्व विवादों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए। उनकी इस पहल का उद्देश्य न केवल जनता को त्वरित न्याय दिलाना है, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देना है। इसी के तहत प्रदेश के जिलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी पूरी तत्परता से मामलों का निस्तारण कर रहे हैं। राजस्व परिषद की आरसीसीएमएस की अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में पूरे प्रदेश में कुल 3,69,293 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि सबसे अधिक राजधानी लखनऊ में 19,178 मामलों का निस्तारित कर पूरे प्रदेश में दूसरे, गोरखपुर 9,560 मामलों को निस्तारित कर तीसरे स्थान पर है। इसी तरह जौनपुर ने 8,779 ...शेष पृष्ठ 14 पर

बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज सीओ, इंस्पेक्टर नपे

मुख्यमंत्री योगी ने दिये जांच के आदेश जिला संवाददाता बाराबंकी। जिले में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में छात्रों पर किए गए लाठी चार्ज के मामले में कोतवाल आर के राना को जहां लाइन हाजिर कर दिया गया है, वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्षित चौहान को भी हटा दिया गया है। मसौली थाने के इंस्पेक्टर सुधीर सिंह को नगर कोतवाली का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। विद्यार्थियों का आरोप है कि श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय ने उन्हें एक ऐसे विधि पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाया, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं है, ऐसे में उनका भविष्य खतरे में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या के मंडल्युक्त को उक्त विश्वविद्यालय की डिग्री की वैधता की जांच करने और अयोध्या क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तर) विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस की मानें तो इसी बात को लेकर सोमवार को विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने पास की एक पुलिस चौकी और परिसर में तोड़फोड़ ...शेष पृष्ठ 14 पर

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति मंजूर, यूपी बनेगा ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। प्रदेश सरकार अगले 6 साल तक डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी जैसे 11 महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट्स के निर्माण को बढ़ावा देगी। योगी सरकार की इस नीति से 5,000 करोड़ रुपये के निवेश और लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने

● नई नीति से 5,000 करोड़ रुपये के निवेश और लाखों को मिलेंगे रोजगार

कैबिनेट के फैसले

की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेन्ट मैनुफैक्चरिंग स्क्रीम के अनुरूप विनिर्माण नीति-2025 को लागू करने का फैसला किया, जो 1 अप्रैल, 2025 से 6 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत उद्यमियों को केंद्र की योजना के समतुल्य अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे यूपी का मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम ग्लोबल

मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। नीति का क्रियान्वयन शासन स्तर पर गठित नीति कार्यान्वयन इकाई और सशक्त समिति की देखरेख में नोडल संस्था द्वारा किया जाएगा। इसके तहत डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी जैसे कॉम्पोनेन्ट्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 2015 में जहाँ केवल 2 यूनिट मोबाइल बनाती थीं, आज 300 यूनिट्स कार्यरत हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का उत्पादन 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। मोबाइल फोन का निर्यात 1,500 करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है। यूपी इस क्रांति का केंद्र बन चुका है, जहाँ देश के आधे से ज्यादा मोबाइल फोन का उत्पादन होता है। यह नीति यूपी को आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह नीति न केवल यूपी को ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब बनाएगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर यूपी की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगी। नीति के तहत 5,000 करोड़ रुपये का अनुमानित



व्यय होगा, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। यह कदम यूपी को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने और औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को दी मंजूरी : उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर निर्यात हब बनाने की दिशा में योगी कैबिनेट ने निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी दे दी है। नई नीति में 2020-25 की निर्यात नीति में सुधार करते हुए डिजिटल तकनीकों, अवसरचं

विकास, वित्तीय सहायता, निर्यात ऋण और बीमा, बाजार विस्तार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि करना और सभी जनपदों को निर्यात गतिविधियों से जोड़कर क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश का निर्यात न केवल गुणात्मक रूप से बढ़ेगा बल्कि उत्तर प्रदेश को एक सशक्त ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

शाहजहांपुर में स्वामी

शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की होगी स्थापना : यूपी कैबिनेट ने शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए मुख्य आश्रम ट्रस्ट की शैक्षणिक इकाइयों को उच्चिकृत किया जाएगा। वर्तमान में ट्रस्ट के अंतर्गत 5 संस्थान संचालित हैं—स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज, स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय, श्री देवी सम्पद ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय, श्री धर्मानन्द सरस्वती इंटर कॉलेज और श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ। विश्वविद्यालय बनने

लखनऊ और कानपुर में नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर संचालित होगी ई-बसें

नगरीय परिवहन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी कैबिनेट ने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर तथा उसके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में ई-बसें को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर संचालित करने की निर्णय लिया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि अभी तक प्रदेश के 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें से 700 बसें ग्रांस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर हैं।

इस योजना के अंतर्गत लखनऊ और कानपुर नगर समेत आस-पास के कस्बों में 10-10 रूटों पर 9 मीटर लंबी एसी ई-बसें चलाई जाएंगी। प्रत्येक रूट पर कम से कम 10 बसें अनिवार्य होंगी। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष की होगी। अनुमान है कि प्रत्येक रूट

पर करीब 10.30 करोड़ रुपये का व्यय आएगा, जिसमें से 9.50 करोड़ रुपये बसें को खरीद पर और 0.80 करोड़ रुपये चार्जिंग उपकरणों व अन्य आवश्यक साधनों पर खर्च होंगे। प्रावधान के तहत, बसें का डिजाइन, वित्तपोषण, खरीद, निर्माण, आपूर्ति और अनुरक्षण को जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर निभाएंगे। उन्हें 90 दिनों के भीतर प्रोटोटाइप ई-बस उपलब्ध करानी होगी और एक वर्ष के भीतर बस संचालन शुरू करना होगा। सभी किराया एवं गैर-किराया राजस्व का संग्रह निजी ऑपरेटर करेंगे। टैरिफ निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा। साथ ही सरकार परिवहन विभाग और आरटीओ/आरटीए से आवश्यक लाइसेंस और परमिट जारी करेगी। ई-बसें के संचालन के लिए सरकार बिहाईड-ड-मीटर विद्युत अवसरचना और अपॉचुनिटी चार्जिंग

की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। सरकार का मानना है कि इस मॉडल से सरकारी वित्तीय बोझ में कमी आएगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

लखनऊ में इन मार्गों पर चलेंगी ई-बसें : चारबाग से बाराबंकी, चारबाग से देवा, चारबाग से कुर्सी, कमता से एयरपोर्ट, बालागंज से मोहनलालगंज, बालागंज से विराज खंड, घंटाघर से माल थाना, घंटाघर से संडीला, स्कूटर इंडिया से ईजीनियरिंग कॉलेज, दुबगा से गंगाजंज

कानपुर के इन मार्गों पर चलेंगी बसें : घंटाघर से अकबरपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिंदकी, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिंदुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से घाटमपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से आईआईटी, घंटाघर से मूसानगर, कानपुर सिटी सर्कुलर रोड, रामा देवी से जहानाबाद, फजलगंज से रूरा, कानपुर रेलवे स्टेशन से उन्नाव।

जमीन 20 एकड़ जमीन विश्वविद्यालय को मिलेगी। पहले चरण में उच्च शिक्षा विभाग और मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट के बीच एमओयू होगा।

इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत औपचारिक कार्यवाही पूरी की जाएगी।

किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट दे रही योगी सरकार

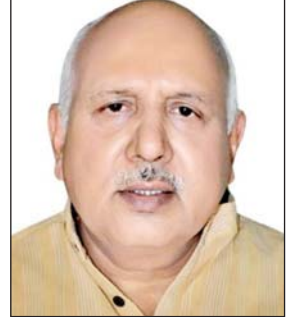
लखनऊ। योगी सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में इस वर्ष भी बड़ा निर्णय लिया है। योगी सरकार रबी 2025-26 के लिए निःशुल्क दलहन-तिलहन की बीज मिनीकिट वितरित करेगी। इसका लाभ प्राप्त

- दलहन-तिलहन के निःशुल्क बीज मिनीकिट के लिए किसान 25 सितंबर तक करें आवेदन
- वेबसाइट पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
- चना, मटर, मसूर व सरसों का दिया जायेगा मिनीकिट
- लक्ष्य से अधिक आवेदन पर लॉटरी के माध्यम से होगा चयन

करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

किसान 25 सितंबर तक बुकिंग व

आवेदन कर सकेंगे। लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से होगा। योगी सरकार द्वारा वित्तपोषित निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट



वितरण व प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को रबी 2025-26 में दलहन की फसलें चना (16 किग्रा.), मटर (20 किग्रा.) व मसूर (8 किग्रा.) के बीज मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं तिलहन

फसल के अंतर्गत सरसों (2 किग्रा.) का बीज मिनीकिट भी दिया जाएगा। कृषि मंत्री सुप्रताप शाही ने बताया कि इन मिनीकिट के लाभार्थियों का चयन लॉटरी पद्धति से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से पारदर्शी ढंग से किया जाएगा।

जो भी किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें कृषि दर्शन-2 पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग-आवेदन करना होगा। आवेदन 25 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। शाही ने बताया कि कृषि विभाग में पंजीकृत किसान ही मिनीकिट के लिए आवेदन व बुकिंग कर सकेंगे। एक किसान केवल एक ही दलहन फसल का मिनीकिट प्राप्त कर सकेंगे। जनपद में लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग अब सेवारत विभाग में शामिल

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को सेवारत विभाग में शामिल करने का फैसला किया है। स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र शास्त्री लखनऊ में शामिल करने का फैसला किया है।

कैबिनेट के फैसले

बताया कि सेवारत विभाग का दर्जा मिलने से विभागीय कार्यालयों के लिए सरकार की अन्य सेवा विभागों की भांति मुफ्त में भूमि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे निजी भवनों के किराये पर होने वाले व्यय में कमी आएगी और जनता को पंजीकरण सेवाएं और अधिक सुलभ वातावरण में मिल सकेंगी। इस निर्णय से विभाग की कार्यकुशलता बढ़ेगी, जनसामान्य



को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा शासन की प्रणाली और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि यह विभाग हर साल करीब 40 लाख रजिस्ट्रेशन करता है। इससे दो करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्राप्त करते हैं। यह विभाग न केवल राज्य सरकार को

विशाल राजस्व प्रदान करता है बल्कि शासन की सामान्य कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा भी है। विभाग किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि नहीं करता, बल्कि सरकार का संवैधानिक दायित्व निभाता है।

दिव्यांगजनों सशक्तीकरण के लिए नया केंद्र : दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए वाराणसी के परगना रामनगर में स्थित 3 एकड़ जमीन को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को सौंपे जाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। इस जमीन पर समेकित क्षेत्रीय केंद्र बनाया जाएगा। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करेगा।

सरकार ने 1607 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी : यूपी कैबिनेट की बैठक में 1607 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी दी गई। देवरिया, शाहजहांपुर, गौतमबुद्धनगर एवं फर्रुखाबाद में चार कम्पनियों को इसके लिए जल्द ही लेटर ऑफ कम्प्टेंजारी होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दो ने कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि वुडेपेकर ग्रीएण्ट्री न्यूट्रिंट्स कंपनी फर्रुखाबाद 570

करोड़ के निवेश करेगी। यह कंपनी बीयर एक्सट्रैक्ट यूटिलिटी इंडियन मेड फारेन लीडर / मक्के का वाणिज्यिक उत्पादन के लिए एक संयंत्र लगाएगी। पहले चरण में उत्पादन एक सितंबर 2026 से होगा। ओकासगंगा एग्रीटेक दादरी (गौतमबुद्धनगर) में 510.20 करोड़ रुपये से अनाज मिल उत्पादन, स्टार्च, एवं स्टार्च उत्पादनों के लिए नया संयंत्र लगाएगी। यहां 31 दिसंबर 2025 से ब्रेड एवं बेकरी उत्पाद बनेंगे। वाईटीटी इंडस्ट्रीज शाहजहांपुर में 277.86 करोड़ के निवेश से अनाज आधारित एथेनाल व पोल्ट्री चार का उत्पादन करेगी। फॉरएच डिस्टिलरी देवरिया में एथनाल एवं एक्सट्रैक्ट यूटिलिटी अल्कोहल उत्पादन के विस्तार के लिए संयंत्र स्थापित करेगी। एक अक्टूबर से उत्पादन चालू करने की तैयारी है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मंगलवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न जिलों आये उलेमा-ए-इक़राम के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उलेमा-

उलेमाओं ने की अखिलेश यादव को दोबारा सीएम बनने की दुआ

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मंगलवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न जिलों आये उलेमा-ए-इक़राम के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उलेमा-

- सपा प्रमुख से मिला उलेमा-ए-इक़राम का प्रतिनिधिमंडल

ए-इक़राम ने अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनने की दुआ की।

इस अवसर पर उलेमा-ए-इक़राम में एक स्वर में अखिलेश यादव के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहा कि हम यकीन से यह बात कहते हैं कि आप नेताजी मुलायम सिंह यादव के नवसे कदम पर चल रहे हैं। हम सभी लोग पूरी तानत से सपा के साथ हैं। अखिलेश यादव ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सपा का सभी से एक भावनात्मक रिश्ता है। इस



अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा हो गयी है। कानून का राज नहीं रह गया है। निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। माँब लिंगिंग में हत्याएं हो रही हैं। पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं। भाजपा सरकार अपने राजनीतिक

फायदे के लिए पुलिस का गैरकानूनी इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कमजोर करने में सपा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2027 में सपा भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। भाजपा को सत्ता से बाहर करना ही देश हित में है। सपा की सरकार

लोकतंत्र, संविधान और वोट का अधिकार बचाने के लिए भाजपा से सावधान रहना होगा। भाजपा नफरत और साम्प्रदायिकता को राजनीति करती है। भाजपा चुनाव में हर स्तर पर बेईमानी करती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना होगा। बूथ को और मजबूत करना होगा।

कार्यकर्ताओं का काम बहुत बढ़ गया है। वोट बचाना, वोट बचाना, वोट पड़वाना और वोट गिनवाना। हर काम को पूरी मेहनत और जागरूकता से करना होगा।

समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी तथा प्रदेश अध्यक्ष मो. शकील नदवी के साथ अखिलेश यादव से भेंट-कर्ताओं में प्रमुख रूप से मौलाना आरिफ (जहूर कासमी), राव करी सलीम देववंद, मौलाना अब्दुल हलीम साहब, मौलाना अशरफ साहब, मौलाना इकबाल साहब, मौलाना मुफ्तखा, मौलाना शमशाद, मौलाना उमैर, मुफ्ती मोहम्मद मुदरिस, बहरोज आलम (जहूर कासमी), करीमो. असागर, मौलाना आलिशाज साहब आदि थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरमम नंदा राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल तथा तेजेंद्र विकी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

दो सितंबर का दिन राज्य आंदोलन के इतिहास में काले अध्याय के रूप में रहेगा अंकित : धामी

सीएम धामी ने मसूरी में वैंडर जोन बनाने और गढ़वाल सभा का भवन बनाने की घोषणा की

प्रमुख संवाददाता

देहरादून। दो सितंबर का दिन सदैव राज्य आंदोलन के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। वर्ष 1994 में इसी दिन मसूरी की वीरभूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस

- मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

को गोलियों का सामना करना पड़ा। यह घटना उस समय के सत्ताधारी दलों के दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया।

यह विचार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किया।



मुख्यमंत्री ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का

उत्तराखंड बनाने के लिए कृतसंकल्प होकर कार्य कर रही है। मसूरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मसूरी में शहीद हुए आंदोलनकारी

की सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। साथ ही

शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा भी शुरू की गई है। घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड बने जहाँ हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित कर दिए हैं। वहीं, प्रदेश के युवाओं को पारदर्शिता के साथ रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करने के लिए देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया गया और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया। इसके बाद उत्तराखंड में 25 हजार से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियों

पाने में सफलता प्राप्त की है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गढ़वाल सभा भवन जल्द बनाने और सिफन कोर्ट का मामला जल्द हल करने की बात कही तथा मसूरी में वैंडर जोन की घोषणा सहित अन्य मांगों पर भी शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी के जन्मशताब्दी समारोह को भी भव्य तरीके से मनाएगी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी तहसील बनाने के लिए सीएम का आभार व्यक्त करने के साथ ही मसूरी की विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, दजाधारी सुभाष बड़धवाल, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन मल्ल सहित राज्य आंदोलनकारियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी शामिल हुए।

अखिलेश यादव को किया गया सम्मानित

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मंगलवार को हाजी उसामा अंसारी अध्यक्ष बुनकर मोमिन अंसार एसोसिएशन बाराबंकी, शोएब सिद्दीकी, हारून राईन अध्यक्ष राईन समाज तथा मोहम्मद वसीम सिद्दीकी जिला सचिव सपा बाराबंकी ने भेंट कर उनको सम्मानित किया। बुनकर समाज के प्रतिनिधियों ने अखिलेश यादव के प्रति कृतज्ञता जताते हुए कहा कि सपा की सरकार को बुनकरों को फ्लैट टेट पर विद्युत व्यवस्था का लाभ मिलता था। आज भाजपा सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। वह भी नियमित और निर्बाध रूप से नहीं मिलती है। समाजवादी सरकार में बुनकरों के लिए बाजार बनाए थे। लखनऊ में अवध शिल्पमय तथा अवध बाजार बनाए गए थे ताकि उद्यमियों के उत्पाद का आसानी से विक्रय हो सके। उन्होंने कहा कि बुनकर समाज 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने सभी बुनकर प्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए कहा कि बुनकर और राईन समाज पीडीए का हिस्सा है। बुनकरों की समस्याओं से वे अवगत हैं। बुनकरों को न्यूनतम ब्याज पर ऋण की सुविधा मिलनी चाहिए। पावरलूम के लिए बिजली सस्ती और समय से मिलनी चाहिए।

संक्षेप

बालक व युवक की सर्पदंश से मौत



प्रतापगढ़। जहरीले जन्तु के डसने से तेरह वर्षीय बच्चे तथा सर्पदंश से युवक की मंगलवार को मौत हो गयी। मासूम व युवक की मौत से पीड़ित परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सांगीपुर थाना क्षेत्र के लखनसूरपुर निवासी संजय सरोज 28 पुत्र सोहनलाल सोमवार की रात खाना खाकर कमरे में सो रहा था। रात लगभग बारह बजे युवक ने स्वजनों को जगाकर बताया कि उसे सांप ने डस लिया है। परिजन आननफानन में उसे झाड़फूक कराने ले गये। इसके बावजूद युवक की तबीयत और खराब होती गयी तब उसे सांगीपुर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में ही युवक की मौत हो गयी। मृतक अपने पीछे दस वर्षीया पुत्री सोनाक्षी तथा आठ वर्षीय मासूम प्रियांशु व पत्नी कृष्णा को निर्मात छोड़ गया है। इधर लालगंज कोतवाली के गौसपुर निवासी राजाराम यादव के तेरह वर्षीय पुत्र राज यादव को घर में सोते समय सोमवार की रात जहरीले जन्तु ने डस लिया। जानकारी होने पर परिजन बच्चे को ट्रामा सेण्टर ले आये। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में ही राज की मौत हो गयी। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया।

गैंगस्टर का आरोपी धरया, गसा जेल

प्रतापगढ़। कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी को धर दबोचा है। कोतवाली में तैनात आरक्षी माधवेश राय व ऋषिराज यादव मंगलवार की सुबह गश्त पर निकले थे। इस बीच सराय जगत सिंह डिहवा निवासी गैंगस्टर के बांछित अमृतलाल पुत्र जियालाल को गश्ती पुलिस ने राजेन्द्र नगर चौराहा के समीप से हिरासत में ले लिया। पकड़े गये आरोपी अमृतलाल के खिलाफ पारको व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में पांच केस दर्ज हैं। सफलता पर लालगंज सीओ आशुतोष मिश्र ने दोनों आरक्षियों को एस्पपी द्वारा निरक्षर पुरस्कार व उच्च प्रवृद्धि दिये जाने की बात कही है। वहीं मारपीट की घटना में वांछित आरोपी को भी मंगलवार की सुबह लालगंज पुलिस ने धर दबोचा। कोतवाली के दोषी गणेश विवेक कुमार फोर्स के साथ गश्त पर निकले थे। नरायणपुर गांव में आरोपी मोतीलाल पुत्र कल्लू सरोज पुलिस के हथ्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

चौरों ने उड़ाये 35 हजार नकदी समेत जेवरत

प्रतापगढ़। सांगीपुर थाना क्षेत्र के पूरे मुरली नौबस्ता में अज्ञात चौरों ने बीती सोमवार की रात चोरी की घटना अंजाम दी। गांव के महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि घटना की रात चौरों ने उसके घर से महिलाओं के सोने चांदी के जेवरत व पैतृस हजार रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने घटना की सूचना सांगीपुर पुलिस को दी है। सांगीपुर एसओ मनीष त्रिपाठी का कहना है कि घटना की जांच कर शीघ्र खुलासा किया जाएगा।

खाद की कमी से नाराज सपाइयों ने किया विरोध प्रदर्शन

प्रतापगढ़। जिले में यूरिया खाद की कमी को लेकर नाराज सपाइयों ने मंगलवार को तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। सपा नेता संजीव पटेल व प्रवीण यादव की अगुवाई में कार्यकर्ता नारेबाजी करते तहसील परिसर पहुंचे। यहां विरोध प्रदर्शन के दौरान संजीव पटेल ने कहा कि धान की खेती के समय यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम शैलेन्द्र वर्मा से मिलकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। एसडीएम ने कार्यकर्ताओं को समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर रामधन यादव, रोशनलाल सरोज, अजय प्रताप यादव, विमल कुमार यादव, अभिषेक यादव, राजेश कुमार कोरी, अरविंद कुमार, शिव कुमार कनौजिया आदि रहे।

चीन अविश्वसनीय पड़ोसी : मोना

- कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में लड़ाई तेज करने का क्विया आह्वान

प्रतापगढ़। क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आरधना मिश्रा मोना ने पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर मंगलवार को ताजी घेराबंदी की है। उन्होंने कहा है कि चीन एक अविश्वसनीय एवं खतरनाक पड़ोसी है। सीएलपी नेता यात्रा के दौरान अपने समकक्ष के सामने लददाख में शहीद हुए इन्कीस भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि के साथ यह मुद्दा गंभीरता से उठाने का साहस नहीं मीडिया से बावचोत में विधायक मोना ने कहा कि चीन के द्वारा भारतीय बाजारों को लगातार मुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के स्वदेशी नारे के विपरीत चीन का देश में बढ़ता आयात अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंताजनक हालात बनाये है। उन्होंने बिहार में राहुल गांधी की मदतदा अधिकार यात्रा को पूरी तरह से सफल भी करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा के इशारे पर बिहार में मदतदा सूची से पैसठ लाख लोगों के नाम हटाने की लड़ाई लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की



मजबूती को लेकर शुरू की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी क्रोमत पर देश भर में वोट चोरी के सहारे सत्ता पर काबिज रहने की बीजेपी की खतरनाक मंशा को पूरा नहीं होने देगी। वहीं उन्होंने कहा कि एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में चीनी परियोजना बीआरआई पर शेष अन्य आठ सदस्य देशों का समर्थन करना भी पीएम के चीनी दौरे को असहज बना गया है। वहीं कैम्प कार्यालय पर संगठन सुजन अभियान के तहत त्रिभुज मोना ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर तगड़े संघर्ष का आह्वान किया है। विधायक आरधना मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा किसानों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद की आपूर्ति में सरकार के ढेर झूठे दावे की कलई पूरी तरह खुल गयी है। उन्होंने

कहा कि धान की फसल बचाने के लिए किसान समितियों तक पर इस समय कालाबाजारी की असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि नहरों में अभी तक टेल तक पानी पहुंचाने में भी सरकारी प्रबन्धन पूरी तरह असफल है। विधायक आरधना मिश्रा ने कहा कि बिजली आपूर्ति बेपटरी पर है और स्मार्ट मीटर के नाम पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को परेशान का जा रहा है। कार्यकर्ताओं को वरुंचुअल संबोधित करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने विधायक मोना के नेतृत्व में यहां संचालित सुदृढ़ विकास की मजबूती में योगदान पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष केडी मिश्र व संयोजन ब्लाक प्रमुख ई. अमित प्रताप सिंह पंकज ने किया। संचालन मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने किया।

डीएम ने कस्तूर बा विद्यालय का क्विया निरीक्षण

- निरीक्षण के दौरान डीएम ने खाने की गुणवत्ता खाकर चेक की, खाने की गुणवत्ता मिली खराब

शोहरतगढ़-सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासिय बालिका विद्यालय, परसिया, विकास खण्ड शोहरतगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण जिलाधिकारी ने कक्षा 6 एवं 7 के बच्चों से वार्ता किया गया तथा जानकारी प्राप्त

चेक किया गया। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया गया। दोपहर के नास्ते में मौके पर सूखी सब्जी, चावल, दालमिला, इसके साथ ही खयता और सलाद न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया गया। भण्डार कक्ष को देखा गया। भण्डारण कक्ष में गन्दगी पाये जाने पर कड़ी

नाराजगी व्यक्त करते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी शोहरतगढ़ का स्पष्टीकरण तथा प्र0 वार्डन नीलम चतुर्वेदी, मृदुलेश, रूबी यादव, सरिता, प्रीती जायसवाल, चन्दा कुमारी तथा लेखाकार विनय कुमार सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया।

साधन सहकारी समिति गुजरौलिया का औचक निरीक्षण



सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 ने गत मंगलवार तहसील शो0 / विकास खंड शोहरतगढ़ के साधन सहकारी समिति गुजरौलिया (करहिया) का औचक निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण जिलाधिकारी ने स्टाक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर का मिलान किया गया। स्टाक सही पाया गया। इसके साथ जिलाधिकारी ने किसानों से स्वयं संचालित कर आधार, खतौनी आदि को देखा गया। जो कि सही पाया गया। जिलाधिकारी ने सम्बंधित को निर्देश दिया कि नियमानुसार खाद का वितरण कराये व किसानों को धरातल पर लाभ पहुंचाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया।

जन-जन तक पहुंचें स्वास्थ्य सुविधाएं : डीएम

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति बैठक सम्पन्न



श्रावस्ती। जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक 2 सितंबर सायंकाल कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ क्रियान्वयन कर जनपद की रैकिंग में उल्लेखनीय सुधार लाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने हेतु कारगर रणनीति

अपनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी परिस्थिति में गर्भवती/धात्री महिलाओं अथवा नवजात शिशुओं को मृत्यु केवल स्वास्थ्य उपेक्षा के कारण न हो। इसके लिए आर0सी0एच0 पोर्टल पर पंजीकरण एवं अपडेशन शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्दिशित किया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाना प्रशासन का संकल्पबद्ध लक्ष्य है।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्मजात दोषग्रस्त बच्चों को चिन्हित कर त्वरित चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार कराया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने विभागीय प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जननी सुरक्षा योजना में लक्ष्य प्राप्ति स्वास्थ्य विभाग की भूमिस्थ कार्यकुशलता को दर्शाती है। बैठक का संचालन डी0सी0पी0एम0 राकेश गुप्ता ने किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अशोक कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 वी0के0 श्रीवास्तव, डब्ल्यूएच0ओ0 के एस0एच0ओ0, यूनिसेफ प्रतिनिधि, समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, हेल्थ पार्नर्स एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

तिरंगे से ऊंचा फहराया इस्लामी झंडा, इमाम के खिलाफ केस दर्ज

कोशांबी। पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज से अधिक ऊंचा इस्लामी झंडा फहराने के आरोप में मामला दर्ज किया है। चावल क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह घटना 31 अगस्त को संदीपन घाट थाना क्षेत्र की है। उन्होंने बताया कि मूरतगंज चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक अजीत सिंह ने क्षेत्र में गश्त के दौरान देखा कि कस्बे में एक मीनारा मस्जिद के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समान इस्लामी झंडा उससे ऊंचाई में अधिक लगाया गया था। इससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मौके से इस्लामी झंडे को हटाया दिया गया है और चौकी प्रभारी की तहरीर पर संदीपन घाट थाने में मस्जिद के इमाम इम्तिवाज अहमद के खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जाएगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में मादक पदार्थ और मानव रस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसवी और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाए जाएंगे और आमजन को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा को भी अहम बताया है।

श्रावस्ती नेटवर्क सुधार के लिए दहान मिश्रा की पहल



श्रावस्ती। जनपद श्रावस्ती के पूर्व सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष दहन मिश्रा ने राजधानी दिल्ली में भारत सरकार के दूरसंचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की दुर्बल नेटवर्क अवसंरचना और संचार अवरोध से जुड़ी गंभीर स्थिति पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दहन मिश्रा ने कहा कि श्रावस्ती जैसे सीमांत जनपद में आज भी अनेक गांव डिजिटल परिदृश्य से वंचित हैं। मोबाइल टॉवरों की अपर्याप्तता तथा प्रौद्योगिकी अवरोध के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण नागरिकों को संवाद-संपर्क में कठिनाई, ऑनलाइन शिक्षा में व्यवधान, ई-गवर्नेंस योजनाओं में अड़चन तथा डिजिटल लेन-देन में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया परिकल्पना का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब सुदूरवर्ती अंचलों में सुदृढ़ संचार अवसंरचना उपलब्ध कराई जाए। मिश्रा ने मांग की कि श्रावस्ती सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में नवीन टेलीकॉम टॉवर स्थापित किए जाएं और वर्तमान टॉवरों की क्षमता परिष्कृत की जाए। मंत्री डॉ. पेमासानी ने गंभीरता से इस विषय पर सुनवाई की और आश्वासन दिया कि मंत्रालय शीघ्र ही कारगर कार्ययोजना बनाकर समस्या का समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार डिजिटल समावेशन और तकनीकी प्रगति को लेकर पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात से श्रावस्ती जनपद के नागरिकों में आश्वस्त की भावना जगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि संचार तंत्र सुदृढ़ हो जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन और सामाजिक संवाद में नई ऊर्जा आएगी। दहन मिश्रा की पहल को लोग सकारात्मक संकल्प, जनसरोकार की प्रतिबद्धता और सार्वजनिक नेतृत्व का उक्तूट उदाहरण मान रहे हैं।

मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाशों पर जानलेवा हमले का केस दर्ज, तीसरे की तलाश में जुटी पुलिस

प्रतापगढ़। पिछले सप्ताह शनिवार को घर जा रहे मजदूर लालगंज कोतवाली के पूरे वंशी निवासी उमापति वर्मा के साथ मोबाइल छिनेती व फायरिंग को लेकर मुठभेड़ में दबोचे गये दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में फरार हुए तीसरे आरोपी भदारी कला निवासी अभिषेक यादव पुत्र लालजी यादव की तलाश में मंगलवार को मशक्कत करती देखी गयी। शनिवार को पूरे वंशी निवासी उमापति वर्मा शाम घर पैदल वापस लौट रहा था। तीन बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनेते हुए जानलेवा फायर झोक दिया था। सोमवार की देर शाम बदमाशों की तलाश में लालगंज पुलिस को स्पेशल टीम के साथ दो बदमाशों को मुठभेड़ में घायल कर हिरासत में लेने में सफलता मिल गयी। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार व स्पेशल टीम प्रभारी अर्जुन सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने साहसिक मुकाबला करते हुए सांगीपुर थाना के हर्षपुर खुशहट निवासी राहुल यादव पुत्र रामराज यादव तथा इसी थाना क्षेत्र के हर्षपुर कोटवा निवासी राजेन्द्र यादव पुत्र शारदा प्रसाद यादव को मुठभेड़ में धर दबोचा। दोनों दबोचे गये बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगी है। महज छत्तीस घंटे में पुलिस ने छिनेती के आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस की सफलता की जानकारी पर एएसपी संजय राय भी लालगंज ट्रामा सेंटर पहुंचे। एएसपी ने प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार व स्पेशल टीम प्रभारी अर्जुन सिंह को एस्पपी से पुरस्कार की संस्तुति की है। वहीं लालगंज कोतवाली प्रदीप को तहरीर पर मुठभेड़ में घायल राहुल यादव व राजेन्द्र के खिलाफ देर रात पुलिस टीम पर फायरिंग के द्वारा जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब फरार तीसरे आरोपी अभिषेक यादव की तलाश में जुटी हुई है। लालगंज सीओ आशुतोष मिश्र ने बताया कि पुलिस टीम में आरोपी की तलाश कर रही है, शीघ्र ही उसे दबोच लिया जाएगा।

क्र० सं०	भवन संख्या	दर्ज भवन स्वामी का नाम	जिसके नाम होना है	आधार
1.	एल / 073 / ई एलडीए कालोनी सेक्टर ई वार्ड विद्यावती प्रथम	सनेहलता गुप्ता	उमा गुप्ता पत्नी स्व० ओमप्रकाश गुप्ता	रजिस्ट्री व पारिवारिक
2.	सी / 043 एलडीए कालोनी कानपुर रोड सेक्टर - एफ वार्ड विद्यावती प्रथम	विरेंद्र कौर व त्रिलोचन सिंह	नेहा अरोरा पुत्री स्व० विजय जलोटा	रजिस्ट्री
3.	एन-1 / 090ए सेक्टर-एन-1 वार्ड विद्यावती प्रथम	हरीश चन्द्र C/O प्रवीण कुमार	प्रवीण कुमार पुत्र हरीश चन्द्र	दान-विलेख
4.	एन-251 आशियाना सेक्टर-एन वार्ड विद्यावती प्रथम	आमा जम्बेकर, डी०बी० जम्बेकर	देवाशीष बन्दोपाध्याय पुत्र श्री समरेन्द्र कुमार बन्दोपाध्याय	रजिस्ट्री
5.	एन-1 / ई-524 सेक्टर एम-1 आशियाना वार्ड विद्यावती प्रथम	नबी रसूल	श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री भुवन चन्द्र	रजिस्ट्री
6.	एम-156 आशियाना सेक्टर एम वार्ड विद्यावती प्रथम	के०एस० श्रीवास्तव	श्रीमती रजुका यादव पत्नी श्री मानवेन्द्र	रजिस्ट्री
7.	एम-1 / ई-271 सेक्टर एम-1 आशियाना वार्ड विद्यावती प्रथम	राजीव कुमार व आशा सोनी	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री शशि कांत	रजिस्ट्री
8.	एम-ई-405 आशियाना सेक्टर एम वार्ड विद्यावती प्रथम	श्रीमती किष्ण श्रीवास्तव	श्री रमा शंकर त्रिपाठी पुत्र श्री राम मूर्ति	रजिस्ट्री
9.	एम-594 आशियाना सेक्टर एम वार्ड विद्यावती प्रथम	राम रतन व शिखा श्रीवास्तव	श्री उत्कर्ष शर्मा व श्रुति शर्मा	दान विलेख व पारिवारिक
10.	एम-1035 आशियाना सेक्टर एम वार्ड विद्यावती प्रथम	शशि कला गुप्ता पत्नी स्व० एम०एल० जायसवाल	श्री अंकित जायसवाल व श्रीमती प्रीती जायसवाल	दान विलेख
11.	एम-164 आशियाना (सेक्टर एम) वार्ड विद्यावती प्रथम	रजनीश शर्मा	श्री सुरेश कुमार व श्रीमती शशि प्रभा	लेख पत्र
12.	एम-316 (ए) आशियाना सेक्टर-एम वार्ड विद्यावती प्रथम	रतन कुमार नाथ	श्रीमती आशा नाथ पत्नी स्व० रतन कुमार नाथ	पारिवारिक
13.	ई-145 एलडीए कालोनी सेक्टर ई वार्ड विद्यावती प्रथम	रवि यादव पुत्र स्व० राम विलास	श्रीमती रविन्द्र पाठक पत्नी श्री संजय पाठक	लेख पत्र
14.	एम-706 ए आशियाना सेक्टर एम वार्ड विद्यावती प्रथम	मुन्नी देवी अग्रवाल	श्री विनीता राजीव पत्नी श्री राजीव कुमार सिंह	दान विलेख
15.	DFA-601(ANSAL-ORCHID) आशियाना सेक्टर एम वार्ड विद्यावती प्रथम	हरकरन सिंह बेदी व गुरमीत सिंह बेदी	सुमिति वर्मा पत्नी अभिनव सिंह बेदी	रजिस्ट्री
16.	डी-1 / 032 / ई एलडीए कालोनी सेक्टर ई वार्ड विद्यावती प्रथम	भूपेन्द्र सिंह	श्री अनमोलक सिंह पुत्र भूपिंदर सिंह	रजिस्ट्री
17.	डी-1 / 031 / ई एलडीए कालोनी सेक्टर ई वार्ड विद्यावती प्रथम	रविन्द्र कुमार शर्मा	श्री अनमोलक सिंह, श्रीमती जसप्रीत कौर	रजिस्ट्री
18.	एम-814 आशियाना सेक्टर एम वार्ड विद्यावती प्रथम	ए एन सक्सेना	श्रीमती मीलम सक्सेना पत्नी श्री अनन्त नारायण सक्सेना	पंजीकृत वसीयत
19.	DFA-105 आशियाना सेक्टर एम वार्ड विद्यावती प्रथम	गणेश यादव, संजू यादव	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, श्रीमती प्रतिभा मिश्रा	रजिस्ट्री
20.	डी-1 / 009 / ई कालोनी एलडीए सेक्टर ई वार्ड विद्यावती प्रथम	विरेंद्र कुमार	श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री अखिलेश कुमार शर्मा	लेख पत्र
21.	एसएसए / 027 / ई एलडीए कालोनी सेक्टर ई वार्ड विद्यावती प्रथम	वीना देवी	श्री विवेक कुमार पुत्र श्री भोलानाथ	रजिस्ट्री
22.	584 / 423-4 किला मोहम्मदी वार्ड विद्यावती प्रथम	श्रीमती प्रज्ञा शुक्ला	श्री सवन कुमार शाक्य पुत्र मनोहर लाल	रजिस्ट्री
23.	एन-605 आशियाना सेक्टर एन वार्ड विद्यावती प्रथम	के०आर० हंस व सुदर्शन हंस	श्री अभित कुमार तोनर व श्री राहुल चौधरी	रजिस्ट्री
24.	एल / 193 / ई एलडीए कालोनी सेक्टर ई वार्ड विद्यावती प्रथम	अमित कुमार पाल	अरविन्द कुमार कुलवन्त पुत्र श्री सिद्धराम	रजिस्ट्री

जीएसटी घटने से छोटे व्यवसायों को होगा लाभ

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनायेंगे : सीतारमण

चेन्नई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खुल एवं पारदर्शी बनाएंगे। इससे अनुपालन बोझ में और कमी आएगी एवं छोटे व्यवसायों को लाभ होगा।

तमिलनाडु स्थित सिटी यूनिन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक कार्यक्रम के गठन की घोषणा की है। इसका स्पष्ट उद्देश्य निम्नों को सरल बनाना, अनुपालन लागत कम करना तथा स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों और उद्यमियों के लिए एक अधिक अनुकूल परिवेश का निर्माण करना है। सीतारमण ने कहा, इसके अतिरिक्त, अगले दो दिन होने वाली परिषद की बैठक के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की योजनाबद्ध शुरुआत से आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुली



एवं पारदर्शी हो जाएगी। अनुपालन बोझ में और कमी आएगी जिससे छोटे व्यवसायों के लिए फलने-फूलना आसान हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़े सुधारों की घोषणा की थी और नागरिकों के लिए दिवाली पर

बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाने व विविध आवश्यकताओं को पूरा करने का आह्वान किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए बैंकिंग क्षेत्र का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इस परिवर्तन के मार्गदर्शक सिद्धांत विश्वास, प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता होने चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने साथ ही कहा कि पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं जिनमें कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये है। इनमें से अधिकतर खाताधारक महिलाएं हैं। सीतारमण ने यह भी बताया कि भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने परिष्पति गुणवत्ता में बड़ा सुधार दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने 18 वर्षों में पहली बार देश की दीर्घकालिक साख्त में सुधार किया है। मंत्री ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) 31 मार्च, 2025 तक घटकर 2.3 प्रतिशत रह गया है, जबकि शुद्ध एनपीए 0.5 प्रतिशत है। मैं समझती हूँ कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हमारे बैंकों के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि है।

डिजिटल साक्षरता, वित्तीय जागरूकता को लेकर चुनौतियां अब भी बरकरार: राष्ट्रपति

चेन्नई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति के बावजूद, लोगों को अब भी डिजिटल साक्षरता और वित्तीय जागरूकता के संदर्भ में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ने तमिलनाडु स्थित सिटी यूनिन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए।



बैंक और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों वंचित समुदायों के लिए उनके अनुकूल मोबाइल एप्लिकेशन और बीमा उत्पाद प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भुगतान बैंक, डिजिटल चॉलेंज और बैंकिंग प्रतिनिधियों ने वित्तीय सेवाओं को दूरदराज के गांवों के घर-घर पहुंचाया है। हालांकि, इस क्षेत्र में प्रगति के बावजूद, डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट पहुंच और वित्तीय जागरूकता के संदर्भ में कई चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सभी पक्षों के संयुक्त प्रयासों से, लोगों को प्रौद्योगिकी, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक एमएसएमई को विकास के इंजन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, समर्थन पर और सस्ता कर्ज, वित्तीय साक्षरता प्रदान करके और कृषि-प्रौद्योगिकी उपायों को समर्थन देकर, बैंक को टिकाऊ और लाभदायक बनाने में मदद कर सकते हैं। बैंक एमएसएमई को विकास के इंजन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, तमिलनाडु की समाज कल्याण एवं महिला सशक्तीकरण मंत्री गीता जीवन, सिटी यूनिन बैंक के चेयरमैन जी महालिंगम, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एन कामकोठी उपस्थित थे।

संक्षेप

धर्मस्थल विवाद में शामिल कार्यकर्ता आरएसएस-भाजपा से जुड़े हैं: मंत्री प्रियंक खरगे

बंगलुरु। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दो कार्यकर्ता गिरिश माननवर और महेश शेट्टी टिमरोडी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े हैं। सूत्रों ने बताया कि ऐसा आरोप है कि धर्मस्थल विवाद के पीछे इन दोनों लोगों का दिमाग है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और जनभावनाएं आहत करने वाले वीडियो बनाने तथा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में माननवर और टिमरोडी के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों दर्ज किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री खरगे ने संवाददाताओं से कहा कि टिमरोडी आरएसएस से हैं। खरगे ने कहा, कर्नाटक विधानसभा में उन्होंने (भाजपा ने) किसके खिलाफ बोलें? क्या वह महेश शेट्टी टिमरोडी नहीं था? यह व्यक्ति आरएसएस से है। आरएसएस भाजपा का गुरु है। ये लोग आरएसएस, विहिप (विश्व हिंदू परिषद) और बजरंग दल में पले-बढ़े हैं। मंत्री ने माननवर के बारे में कहा, वह भारतीय जनता युवा मोर्चा (जिला) के अध्यक्ष हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद और सात अन्य को जमानत देने से इनकार किया

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 के दंगों के पीछे की कथित साजिश से जुड़े युपीए मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य को जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावल और न्यायमूर्ति शल्लिंदर कौर की पीठ ने शरजील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा और शदाब अहमद को जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। नौ

जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रखने के बाद मंगलवार को पीठ ने कहा कि सभी अपीलें खारिज की जाती हैं। विस्तृत आदेश का इंतजार है। आरोपी 2020 से जेल में हैं और उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। अभियोजन पक्ष ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि यह स्वतः-स्फूर्त दंगों का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है, जहां भयावह सोच के साथ पहले साजिश रची गई और सात-समझकर ऐसा किया गया। अभियोजन पक्ष का

प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश थी और केवल लंबी कैद के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने दलील दी, अगर आप अपने देश के खिलाफ कुछ भी करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप बरी होने तक जेल में रहें। हालांकि, इमाम के वकील ने दलील दी कि वह जगह, समय और खालिद समेत सह-आरोपियों से पूरी तरह से अलग थे। वकील ने कहा कि इमाम के भाषणों और व्हाट्सएप चैट में कभी भी भ्रूषण अर्थात् आह्वान नहीं किया गया।

भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने को प्रतिबद्ध: भूपेंद्र यादव

नयी दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि भारत बहुपक्षवाद में विश्वास रखता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विकसित देश इस दिशा में विकासशील देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहे हैं। यादव ने 20वें सीआईआईई सरटोर्नो बिलिटी समिट में एक परिचरचा के दौरान कहा कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक खतरा है। लेकिन इसका सबसे गंभीर प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जो इस संकट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यादव ने कहा कि हमारा पहला रुख



यह है... हमें बहुपक्षीय मंचों पर विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि भारत समस्या का नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा होगा। उन्होंने आगे कहा, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और विकसित देशों ने लंबे समय से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है। मंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी



वाला देश भारत, अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत कई प्रतिबद्धताओं को पहले ही पूरा कर चुका है। भारत इस चुनौती का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन आवश्यक है, और उद्योग को

हरित प्रौद्योगिकी विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। यादव ने कहा कि दुनिया को भारत के विकास मॉडल पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि भारत लगातार प्रतिशत की दर से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक विकास के पुनरुत्थान का नेतृत्व करेगा। मेरे विचार से, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने लक्षित योजना कार्यान्वयन, बुनियादी ढांचे में निवेश, स्थानीय प्रतिबद्धता और बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं पर ठोस उपलब्धियों के माध्यम से नीतिगत परिदृश्य में सतत विकास को सफलतापूर्वक अपनाया है।

भारत-चीन संबंध पट्टी पर लौट रहे हैं: गोयल

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे पट्टी पर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे सीमा मुद्दे सुलझते जाएंगे तनाव कम होता जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग के बीच हुई बैठक में भारत-चीन सीमा मुद्दे के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने पर सहमत बनी है। दोनों नेताओं ने वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में एक-दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को मान्यता देते हुए व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ाने का संकल्प



लिया। गोयल से पत्रकारों ने पूछा कि अगर भारत और चीन अपने संबंधों को फिर से स्थापित कर रहे हैं, तो क्या पीएन3 में डील की गुंजाइश है इस पर उन्होंने कहा कि यह एक एससीओ शिखर सम्मेलन था, जिसमें सभी एससीओ सदस्यों ने भाग लिया। गलत्यों में हमारे सामने एक समस्या थी, जिसके कारण हमारे संबंधों में थोड़ी तलछट आई थी। पुष्टि लगता है कि सीमा मुद्दों का समाधान होने के साथ ही

स्थिति का सामान्य होना एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम है। चीन से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए सभी क्षेत्रों में वर्तमान में सरकारी अनुमोदन लेना अनिवार्य है। यह नीति अप्रैल, 2020 में प्रेस नोट 3 (पीएन3) के रूप में जारी की गई थी। फेरलू उद्योग सरकार से चीन से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए इन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों को आसान बनाने का आग्रह कर रहा है। जुलाई, 2024 में बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बाजार का दोहन करने के लिए चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने का पुरस्कार समर्थन किया गया था।

सरकार ने मानी अधिकांश मांगें, मराठा नेता जरांगे बोले- हम जीत गये

मुंबई। कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को अनिश्चितकालीन अनशन के पांचवें दिन अपनी अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद जीत की घोषणा की जिससे यहां उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार की मंत्रिमंडलीय उप-समिति द्वारा जिन मांगों को स्वीकार किया गया है उनमें पात्र मराठों को कुनबी जाति का होने का प्रमाण पत्र देना भी शामिल है। मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता वाली राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय उप-समिति के साथ

बैठक के बाद जरांगे ने मराठा आरक्षण आंदोलन के लिये प्रदर्शन कर रहे लोगों से कहा, हम जीत गए हैं। विखे पाटिल ने समिति के अन्य सदस्यों शिवेन्द्रसिंह भोसले, उदय सामंत, माणिकराव कोकोटे - के साथ दोपहर में दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे से मुलाकात की और समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए मसौदे पर उनके साथ चर्चा की। आजाद मैदान में ही आरक्षण की मांग को लेकर मराठा कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर हैं। जरांगे ने कहा, अगर महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण की मांग पर सरकारी आदेश (जीआर) जारी करती है तो हम आज रात नौ बजे

तक मुंबई छोड़ देंगे। उप-समिति ने हैदराबाद गजट को लागू करने की जरांगे की मांग को स्वीकार कर लिया और कहा कि कुनबी रिर्काई वाले मराठों को उचित जांच के बाद जाति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जरांगे ने अपने समर्थकों के समक्ष समिति के मसौदा बिंदुओं को पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि समिति ने हैदराबाद राजपत्र के कार्यान्वयन को स्वीकार कर लिया है और तत्काल जीआर जारी किया जाएगा। सतारा गजट का क्रियान्वयन एक महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले दर्ज किये गये।

फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के खिलाफ बीकानेर में मामला दर्ज

जयपुर। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ बीकानेर शहर में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने भंसाली की नयी फिल्म 'लव एंड वॉर' के निर्माण के दौरान धोखाधड़ी, दुर्ययवहार और विश्वासघात का आरोप लगाया है। बीकानेर सदर के सर्कल अधिकारी विशाल जांगिड़ ने बताया कि प्रतीक राज माथुर नामक व्यक्ति ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया है कि भंसाली ने उन्हें लखन प्रोड्यूसर के तौर पर अनुबंध दिया था लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। जांगिड़ के अनुसार माथुर ने भंसाली और उनकी टीम के दो सदस्यों पर आरोप लगाया है कि उन्हें लखन प्रोड्यूसर की जम्मेदारी सौंपने के बाद बिना भुगतान किए प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश के बाद सोमवार को बिछलथाने में भंसाली, अरविंद गिल और उत्कर्ष बाली के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। माथुर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए।

3 मासिक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान
01.07.2025 - 30.09.2025

2.70 लाख जीपी और यूएलबी द्वारा

पीएमजेडीवाई खाता खोलना

पीएमजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई/ एपीवाई के लिए नामांकन

सभी शेष केवाईसी बचत खातों का पुनः केवाईसी करना।

डिजिटल धोखाधड़ी की टोकथाम और अदावी जमा पर जागरूकता सत्र

बैंक खाते में नामांकन अद्यतन

जनसुझा योजना नामांकन, खाता खोलने, पुनः केवाईसी और धोखाधड़ी की टोकथाम के लिए प्रत्येक पंचायत के कैंप की भेंट दें।

आज ही खाता खोलें

निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी निकटतम बैंक शाखा/ बीसी से संपर्क करें।

इस मुहिम में शामिल होकर जानकारी का प्रचार- प्रसार करें। अपना बीमा कराएं।

गतिविधि में शामिल हों। इस संदेश का प्रचार-प्रसार करें। बीमाकृत हों।

बैंक आपके डोरस्टेप पर अवतर का लाभ उठाएं।

ममता बनर्जी से अपील 'द बंगाल फाइल्स' बैन न करने की मांग

विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है, हालांकि संवेदनशील मुद्दा होने पर इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में फिल्म का विरोध किया जा रहा है। अब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक वीडियो जारी कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मैसेज देते हुए फिल्म बैन न किए जाने की मांग की है। विवेक अग्निहोत्री ने सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री जी, यह वीडियो आपके लिए है। मेरी फिल्म दुनिया भर में रिलीज होगी, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बंगाल में इसे बैन कर दिया जाएगा। थिएटर मालिकों पर इतना राजनीतिक दबाव है कि वे फिल्म दिखाने से डर रहे हैं। इसी डर की वजह से 16 अगस्त को हमारा ट्रेलर भी सिनेमाघरों में नहीं दिखाया गया। जब हमने होटल में इसे लॉन्च करने की कोशिश की, तो पुलिस ने आकर उसे रोक दिया। विवेक रंजन अग्निहोत्री का आरोप है कि तुण्मूल काग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ता लगातार इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं और कई फर्जी एकआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से अपील की है कि वह व्यक्तिगत और राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर इस फिल्म को शांतिपूर्वक रिलीज होने दें। अग्निहोत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार की रक्षा करें। उन्होंने याद दिलाया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड में पास कर दिया है और इसे रिलीज करना अब राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने 1200 वर्षों तक गुलामी और अत्याचार झेला है। हमारी संस्कृति, धर्म और कला पर हमले हुए। इसमें सबसे दर्दनाक अध्याय बंगाल का है, जहां डायरेक्ट एक्शन डे और नौआखली नरसंहार जैसे भयानक हादसे हुए। उनका कहना है कि अगर यह घटनाएं न होतीं, तो शायद भारत का विभाजन भी न होता। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया भर में होलोकॉस्ट, गुलामी और हिरोशिमा-नागासाकी की त्रासदी के बारे में हर्ष बच्चा जानता है।



BABU BANARASI DAS EDUCATIONAL GROUP

NBA NATIONAL BOARD ACADEMICAL BOARD

BBDNIIIT (056) - CSE, IT & B.PHARM
BBDITM (054) - CSE, ECE & IT

12500+ More than **1800+** Companies have already hired our Students!
Job offers & still continuing since last 5 years ...

BBD UNIVERSITY Host University for **KHELO INDIA**

ADMISSION OPEN 2025-2026

BBD UNIVERSITY | www.bbdu.ac.in

COURSES OFFERED

- Engineering
- Dental Science
- Hotel Management
- Management
- Computer Applications
- Agricultural Sciences
- Legal Studies
- Basic Sciences
- Media & Communication
- Pharmacy
- Architecture
- Education
- Ph.D. in all Disciplines

Meritorious Scholarships Offered

B.Sc. (Agriculture) 4 Year Full Time Degree Program

- Courses available in Collaboration with IBM
- Minor Degree available in Collaboration with IIT - Mandi

BBDCODS Bachelor of Dental Surgery (4 Year Course & 1 Year Rotatory Internship) | www.bbdcods.edu.in

BDS Bachelor of Dental Surgery (4 Year Course & 1 Year Rotatory Internship) | www.bbdcods.edu.in

M.D.S/Ph.D In all 9 Specialties

BBDITM | AKTU CODE - 054 | www.bbditm.ac.in
B.TECH (CSE, CSE(AI&ML), CSE(DS), IT, ECE, ME, EE, CE) | MBA & M.TECH

BBDNIIIT | AKTU CODE - 056 | www.bbdniiit.ac.in
B.TECH (CSE, CSE(AI&ML), CSE(AI), IT, ECE, EE, ME, CE) | M.TECH, MBA | B.PHARM, M.PHARM, D.PHARM BTEUP CODE- 2746

SCHOLARSHIP @25%
All 4 Years in EE, ME, CE and ECE in AKTU Colleges

AMENITIES

- Auditorium (1000+ Seating Capacity)
- Student's Health Cafeteria
- Transport & Health Services
- Lord Siddhi Ganesha Temple
- In Campus Bank and ATM
- AC & Non-AC Hostels
- BCCI Approved Cricket Stadium
- BBD Security Channel
- 24x7 Security & Wifi
- Fully Campus

TOP RECRUITERS

amazon, Google, IBM, adani, zomato, Grab, accenture, tcs, Infosys, HARMAN, paytm, EY, Capgemini, NEWGEN, wipro, pwc, accenture

BBD City, Ayodhya Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226028 India.
f @kobbdu | @bbduniversity | www.bbdu.ac.in | 0522(6196222/23) 0522(6196300/301/302)